

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-६८२४/२००६

राजेन्द्र प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक: १५.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री जे के गुप्ता, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या- २१६/२००६ पुलिस थाना- देवली, टोंक अपराध अन्तर्गत धारा- ४२०, ४०६ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि विवादित ट्रक अभियुक्त-प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आई सी आई सी आई बैंक से फायनेंस पर क्रय किया गया था, जिसे दिनांक १६.११.२००५ को परिवादी को एक लाख सत्तर हजार रुपये में जरिये इकरारनामा बेचान किया गया, जिसके पेटे एक लाख पांच हजार रुपये प्राप्त कर लिये गये तथा ६५ हजार रुपये बकाया थे। उनका यह भी तर्क रहा है कि इकरारनामों में यह शर्त थी कि उक्त वाहन की २५ हजार रुपये प्रतिमाह की किश्त आई सी आई सी आई बैंक को परिवादी सीधे फायनेंस कम्पनी को अदा करेगा लेकिन उसके द्वारा किश्त अदा न करने पर आई सी आई सी आई बैंक द्वारा उक्त ट्रक को सीज कर लिया गया। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी कि परिवादी न तो बैंक की किश्त अदा कर रहा है और न ही ट्रक उसने अभियुक्त-प्रार्थी को सुपुर्द किया है लेकिन पुलिस द्वारा दीवानी प्रकृति का मामला मानते हुए अन्तिम रिपोर्ट दे दी गयी तत्पश्चात् प्रार्थी- अभियुक्त को बकाया किश्त अदा करनी पड़ी तथा उक्त ट्रक को अभियुक्त-प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया गया उसके उपरान्त भी प्रार्थी- अभियुक्त नियमित रूप से किश्ते अदा कर रहा है। इस तरह उसके विरुद्ध कोई धोखा धड़ी का मामला ही नहीं है। अपितु वास्तव में आपराधिक कृत्य परिवादी नोरतमल मीणा द्वारा किया गया है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के संदर्भ में इतना ही अंकित किया जाना उपयुक्त होगा कि विवादित ट्रक जो कि आई सी आई सी आई बैंक से फायनेंस पर था, को अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा परिवादी को जरिये इकरारनामा बेचान किया गया था, जिसकी २५ हजार रुपये प्रतिमाह की किश्त परिवादी स्वयं द्वारा फायनेंस कम्पनी में अदा करने की शर्त थी तथा विशिष्ट शर्त में यह भी था कि उक्त वाहन की फाइनेंस की किश्त समय पर अदा नहीं किये जाने पर वाहन को विक्रेता- फाइनेंस कम्पनी अपने स्वामित्व में कर लेगा और फाइनेंस कम्पनी की जो भी पेनेल्टी होगी उसे परिवादी स्वयं पेनेल्टी सहित अदा करेगा। उक्त वाहन की किश्त अदा नहीं किये जाने पर वाहन को आई सी आई सी आई बैंक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाना बताया गया है तत्पश्चात् अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा किश्त चुकाकर उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लिया जाना बताया गया है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री फूला राम निवासी- ढाणी सुखावाली तन काट तहसील व थाना शाहपुरा जिला- जयपुर को पुलिस थाना- देवली जिला-टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-२१६/२००६ में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रुपये १०,०००/- (दस हजार रुपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रुपये ५,०००/- -- ५,०००/- (पांच-पांच हजार रुपये मात्र) की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

१. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
२. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
३. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
४. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल )